



कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक - 111 / 12-1(54) मुनिकीरेती, दिनांक - 17 / 07 / 2019  
सेवा मे,

email: cfbhagi-forest-uk@nic.in

फोन/फैक्स-0135-2431159,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,  
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर,  
फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :-

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत नगुण से धरासू एवं कल्याणी से नालूपानी तक लम्बाई 19.4 किमी  
मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु 0.582 हेतु 0.582 हो वन भूमि 30 वर्षों की लीज  
पर दिये जाने के सम्बन्ध में |(FP/UK/Others/31137/2018)

सन्दर्भ :-

आपके द्वारा ऑनलाईन इंगित कमियां दिनांक-14.06.2019 |  
महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में ऑनलाईन आपत्ति इंगित की गयी है कि “*CF may clarify, whatever this RoW --right of way-- has approved under FC clearance at the time of construction*” के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगत कराया गया है कि ऑप्टिकल फाईबर केबिल मोटर मार्ग RoW (right of way) के भीतर ही बिछाई जायेगी। उक्त मोटर मार्ग का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 निर्गत होने से पूर्व किया गया था, जिस कारण वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध नहीं है। किन्तु उक्त मोटर मार्ग की चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किये हैं, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ के पत्र संख्या-08बी/यू०सी०पी०/06/296/2010/एफ०सी०/2272, दिनांक-19.01.2010 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र), देहरादून के पत्र सं-08बी/यू०सी०पी०/06/34/2017/एफ०सी०/1065, दिनांक-22.09.2017 से पूर्व में ही प्राप्त हैं, जो कि आपके अवलोकन हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:-यथोपरि ।

भवदीय

जोशी

(जीवन चन्द्र जोशी)

वन संरक्षक

संख्या :— / , तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को उनके पत्रांक-161/12-1, दिनांक-12.07.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(जीवन चन्द्र जोशी)

वन संरक्षक



भारत सरकार  
पर्यावरण, बन एवं जलवाया परिवर्तन मंत्रालय  
सेन्ट्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र)  
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001  
दूरभाष: 0135-2650809  
फैक्स-0135-2653010  
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &  
CLIMATE CHANGE  
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZON))  
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001  
PHONE- 0135-2650809  
FAX- 0135-2653010  
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं 08वी/यू०सी०पी०/०८/३४/२०१७/एफ०सी० ।।०६५

दिनांक: 22/09/2017

संकेत मे,

सचिव (वन),  
उत्तराखण्ड शासन,  
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : Diversion of 16.971 ha of forest land for rehabilitation and up gradation to 2Lane/2Lane with paved shoulders configuration and strengthening of NH-94 from km 122.00 (Dharasu Band) to Km 147.00 (Silkyara Band) in favour of Ministry of Road Transport and Highways within the jurisdiction of Uttarkashi Forest Division, District Uttarkashi in the State of Uttarakhand (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/24549/2017).

सन्दर्भ : ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/24549/2017 एवं सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 416X-4-17/1(53)/2017 दिनांक 03.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/24549/2017 एवं सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा विषयाकृत प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से यन (सरकार) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्थीकृति मार्गी थी।

इस विषय में मुझ यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियों/ दस्तावेज online मानवाए जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव को Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 11.08.2017 को हुई घेटक में पारित किया गया। REC द्वारा प्रस्ताव को पारित करते हुए वाचित आवश्यक सूचनाओं/ दस्तावेजों के प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार Diversion of 16.971 ha of forest land for rehabilitation and up gradation to 2Lane/2Lane with paved shoulders configuration and strengthening of NH-94 from km 122.00 (Dharasu Band) to Km 147.00 (Silkyara Band) in favour of Ministry of Road Transport and Highways within the jurisdiction of Uttarkashi Forest Division, District Uttarkashi in the State of Uttarakhand हेतु सैद्धान्तिक स्थीकृति निम्नलिखित रूप से पर प्रदान करती हैं:

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 34.00 हेठो Nagungad, Compartment No. 7A बन भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या ५-३/२००७-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
- शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़तारी होती है, तो वही हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या ५-३/२००७-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रदान तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक-11 भूतल, सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा कराया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाए। धनराशि का हस्तान्तरण Online portal के माध्यम द्वारा ही किया जाना आवश्यक है।
- निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ समंज हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर बन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
- State Govt. will provide original hard copy of FRA certificate.

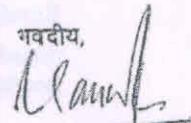
P.T.O.

उपरांकता सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (सरकार) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

संदर्भान्तरक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. एन पी वी की दरों में अगर बढ़ोतारी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण यदी दरों पर एन पी वी देने के लिए वाध्य होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेवर केन्य नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमाकान करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
5. निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैंस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रेख-रेखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
9. कम से कम दृष्टों का कठान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 2915 से अधिक न हो।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निरसारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निरसारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का सतोपज्ञनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

गवर्नर,  
  
(एम.एस.नेगी)  
वन सरकार

#### प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरावार सेड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन सरकार एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर कारेस्ट कालोनी, देहसाढ़ून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

\_\_\_\_\_  
(एम.एस.नेगी)  
वन सरकार